Fishing potentiality in India

2118. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) what measures have been adopted to exploit the fishing potentialities in India;

(b) whether Government propose to create a separate Ministry for this purpose in view it's foreign exchange value; and

(c) if so, when?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Measures adopted to exploit the fishing potentialities are given in the annexed statement.

(b) There is no proposal at present to create a separate Ministry for the purpose of exploiting fishing potentialities in the country.

(c) Does not arise.

Statement

Some of the important measures taken to exploit the fishing potentialities in the country are:—

(1) Raising the productivity of fresh water ponds and tanks through setting up of Fish Farmer's Development Agency (FEDA).

(2) Raising production and productivity in the brackish water potential resources through introduction of extensive, semi-intensive and intensive brackish water fish/prawn farming technology through Brackish Water Fish Farmer's Development Agency (BWEDA).

(3) Shrimp and fish culture project is being launched for development of brackish water resources with World Bank assistance from 1992-93.

(4) Schemes on motorisation of traditional craft, exploitation of off shore pelagic resources through introduction of intermediate crafts, subsidy on high speed diesel used by mechanised fishing vessels etc. are being implemented.

(5) Augmentation of deep sea fishing fleet through judicious mix of indigenous, imported and chartered fishing vessels.

(6) Provision of 33 per cent subsidy on the cost of indigenously constructed deep sea fishing vessels.

(7) Provision of loan facility on soft term by Shipping Credit and Investment Company of India Ltd.

(8) Systematic and intensive survey of fishery resources in Indian Exclusive Economic Zone.

(9) Assistance for construction of fishing harbours at major and minor ports.

(10) Training of deep sea fishing operatives for manning the fishing vessels; and

(11) Regulation of fishing by foreign vessels in the Exclusive Economic Zone and by Indian owned vessels in the Territorial waters.

मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, दिल्ली में गोलमाल की शिकायतें

2119. **श्री मोहम्मद अफजाल उर्फ मीम अफजल :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मोडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, दिल्ली में गोलमाल के संबंध में हाल ही में मिली शिकायतों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध समय-समय पर प्राप्त शिकायतें, कोई कार्रवाई करने से पहले

जांच के लिए जैसी भी स्थिति हो या तो कम्पनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी और /या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जाती है । इसके अनुसार मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध हाल में प्राप्त कुछ शिकायतें इन एजेन्सियों को भेजी गई है ।

Pepsi Soft Drinks

2120. SHRI DIPEN GHOSH: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that orders have been issued that no new approval is to be given by FPO to make Pepsi Soft Drinks;

(b) if so, when;

(c) whether any plant has been licensed after that date and if so, the reasons therefore; and

(d) what other action Government have taken on Pepsi Soft Drinks?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) No. Sir.

(b) to (d) Do not arise.

फल और सब्जियों को प्रसंस्कृत किया जाना

2121. श्री अजीत जोगी :

कुमारी आलिया :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हर साल लगभग 3,000 हजार करोड़ रुपये के मूल्य की सब्जियां और फल बरबाद हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रसंस्कृत किए जाने की सुविधाओं का अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बर्बादी को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ग) देश में उत्पन्न कितने प्रतिशत फलों एवं सब्जियों को प्रसंस्कृत किया जा रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग स्थापित किए गए हैं और उक्त उद्योगों की वजह से किसानों को कितना लाभ पहुंचा है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कौन-कौन से खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित किए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) यद्यपि, कोई प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है फिर भी यह अनुमान है कि अपर्याप्त फसलोत्तर संचालन, प्रसंस्करण कर्त्ताओं और ताजे फल एवं सब्जी बाजारों के साथ सम्पर्क न होने के कारण प्रतिवर्ष 3000 करोड़ मूल्य के फल एवं सब्जियां बर्बाद हो जाती है ।

(ख) इस मंत्रालय ने अनेक योजना स्कीमें तैयार की है जिनके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों, सहकारी समितियों, सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को सहायता दी जाती है जिससे बर्बादी कम से कम हो ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Diversification of Defence purchases

2122. SHRI KAPIL VERMA:

SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what measures are being taken to meet India's need to diversify defence purchases in view of the current problems regarding supply from the Soviet Union;

(b) whether this issue was discussed by the Indian Prime Minister with the French President during the recent visit; if so, the outcome thereof;